वर्ष 3 अंक 6-7 जून-जुलाई 1981 50 पैसे

# सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

# सभी उद्योगों में एक दिन की हड़ताल की तैयारियों पर

● बी. टी. रणदिवे

केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशनों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो 4 जून को बंबई में संपन्न हुआ, ट्रेड यूनियनों के संघर्ष में एक महान घटना होगी यदि राज्यव्यापी सम्मेलन आयोजित करने तथा एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल करने के इसके आह्वान का सभी सच्चे मन से पालन करें. एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल का होना ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक एतिहासिक घटना होगी, यह अभूतपूर्व श्रमिक एकता को घोषणा होगी तथा कांग्रेस (इ) सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ चारों ओर फैले जनवादी और प्रतिरोधात्मक आंदोलन को नया आयाम देगी.

सीटू, इसकी राज्य कमेटियों और इसकी संबद्ध यूनियनों को पूरी कोशिश करनी है कि ये राज्यव्यापी सम्मेलन जनता को एकजुट करने के केंद्र बनें. और इन्हें एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियों में पूरी दक्षता के साथ भाग लेना है.

इस सम्मेलन ने कांग्रेस (इ) सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों को बेनकाब करते हुए कई मुद्दों पर समूची जनता की ओर से आवाज उठाई है.

## महत्वपूर्ण विकास

इसने किसानों के लिए लाभकारी दामों और खेतिहर मजदूरों के लिए बेहतर वेतन की मांग की है. शायद यह पहला मौका है जब विभिन्न राजनीतिक व सैद्धांतिक धाराओं के प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के, जो भारतीय जनता का बहुमत है, समर्थन में आवाज उठाई है. सीटू के अलावा ऐसे बहुत ही कम संगठन हैं जो अपने संविधान में किसानों के लिए समर्थन और मजदूर-किसान एकता की जरूरत के बारे में घोषणा करते हैं. सम्मेलन में एक के बाद एक वक्ता ने किसानों और खेतिहर मजदूरों का समर्थन किया और इस बात की तीव्र इच्छा जाहिर की कि मजदूर वर्ग को खेतिहर मजदूरों को संगठित करने के लिए अगुवाई करनी चाहिए.

पिछले साल के दौरान हुए किसानों के जुझारू संघर्ष का यह असर जरूर था.

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है और यदि इसे आगे बढ़ाया जाता है तो देश में जनवादी तथा निहित-स्वार्थ विरोधी ताकतों की ताकत में भारी बढ़ोतरी करेगा.

## दमनात्मक नीतियों के विरुद्ध

सम्मेलन ने एक बार फिर समूची जनता की ओर से आवाज उठायी जब इसने कीमत-वृद्धि के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और मांग की कि "सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जैसे कि खाद्यान्न, खाद्य तेल, कपड़ा, चीनी, आदि सस्ती कीमतों पर लोकप्रिय कमेटियों के नियंत्रण व देखरेख में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों द्वारा" की जाए.

सम्मेलन ने कांग्रेस (इ) सरकार की दमनात्मक नीतियों के लिए, पहले समझौतों से मुकरने के लिए, इसकी वेतन और आय नीति के लिए, भारी टैक्स लगाने के कदमों के लिए, ठेका व स्थानांतरित मजदूरों के प्रति क्रूर रवैये के लिए, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों पर हमले के लिए, इंटक की तरफदारी के लिए कटु आलोचना की और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वापिस लेने, ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी देने, गुप्तमतदान द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने, छंटनी और क्लोजर पर रोक लगाने, बेकारी भत्ता देने, सभी के लिए बोनस और जरूरत के अनुसार न्यूनतम वेतन देने की मांग की.

इसमें कोई शक नहीं है कि सीटू यूनियनें राज्य सम्मेलनों की तैयारी के दौरान इन मांगों पर मजदूर वर्ग को एकजुट करेंगी.

## भारी हमले

वे समस्यांएं जिनका ट्रेड यूनियन आंदोलन सामना कर रहा है— अधिकारों, जीवन निर्वाह स्तरों पर हमले—कांग्रेस (इ) शासन और इसकी लगातार बढ़ती अधिनायकवादी

[शेष पृष्ठ छः पर]

# एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक स्मरणीय घटना

भारत में संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटना हुई जब 4 जून को बंबई में मूल्यवृद्धि और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन, आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियों और 40 औद्योगिक फेडरेशनों ने आयोजित किया और सम्मेलन ने इसमें उठाई गई मांगों के पक्ष में संपूर्ण भारत में एक दिन की हड़ताल का जोरदार आह्वान किया. सम्मेलन में कांग्रेस (आइ) यूनियन ने भाग नहीं लिया.

मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से और वैतनिक कर्मचारियों, आदि से एक करोड़ मजदूर और कर्मचारियों के 3,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने संमुखानंद हाल को उसकी क्षमता से भी ज्यादा ठसाठस भर दिया और राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों का पक्के तथा दृढ़-प्रण के साथ समर्थन दिया ताकि कांग्रेस (आइ) सरकार मांगों को मानने के लिए मजबूर हो.

## महत्व

सम्मेलन का महत्व यह था कि इससे कांग्रेस (आइ) सरकार की प्रतिक्रियावादी अधिनायकवादी नीतियों के विरुद्ध वैकल्पिक मांगों के आधार पर इंटक के एक हिस्से सहित पूरी मजदूर-शक्ति के ध्रुवीकरण की शुरूआत हो गई है. केवल कुछ विशेष मांगों पर एकजुट होने की सीमा की पार कर, मजदूर वर्ग ने कुछ बुनियादी मुद्दों: भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और मूल्य-वृद्धि की तेज रफ्तार जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यह कामकाजी जनता पर चोट करता है और दोनों समय की रोटी जुटाने में उनके सामने कठिनाइयां पैदा करता है, के विरुद्ध संघर्ष करने पर विचार विमर्श किया. इसका दूसरा महत्व है कि मजदूर वर्ग ने पूरा तहेदिल से बिना किसी शर्त पर किसानों की मांगों का समर्थन किया.

इस तरह अलग-अलग उद्योगों, मालिक, राज्य या प्रांत के स्तर पर संघर्षों की खाई से बाहर निकलकर मेहनतकश लोगों को साथ लेकर भारत में मजदूर वर्ग ने किसानों के साथ मिल कर अधिनायकवादी सरकार के हमलों का सामना करने के लिए एकजुट संघर्ष कार्यक्रम बनाया.

सम्मेलन के प्रांगण का नाम एच. एम. एस. के स्वर्गीय अध्यक्ष की स्मृति में बाल दंडवते नगर रखा गया.

एक अध्यक्ष मंडल जिसके सदस्य थे : समर मुखर्जी (सीटू), ए. बी. बरधान (एटक), एन. सी. गांगुली (बी. एम एस.), डी. डी. वशिष्ट (एच. एम· एस.) श्री कांतन नायर (यू. टी. यू. सी·), जे· एस. दारा (इंटक), ज्ञानसिंह (यू. टी. यू. सी. एल. एस) और एस. डी. पालीवाल (टी. यू. सी. सी) ने सम्मेलन का संचालन किया.

## सबसे बड़ी दोषी

शहीदों और कामरेड बालदंवते पर प्रस्ताव के बाद सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकार अपनी एकाधिकारवादी, सबसे घिनौनी अपराधी है. घाटे का बजट, अप्रत्यक्ष कर जैसे एक्साइज ड्यूटी, कालाधन और मुद्रास्फीति, मूल्य में वृद्धि करने के लिए और लोगों को लूटने के लिए लगातार हथियार है. एकाधिकारियों और सामंतों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने अब मीसा के दूसरे नाम—राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बनाया है.

सीटू के महासचिव ने इसे और विस्तार से बताते हुए कहा कि सरकार ने सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हड़ताल के अधिकार. नौकरी सुरक्षा और और मजदूरों से संबंधित हर अधिकार की जड़ों पर चोट पहुंचाकर चारों तरफ से हमले करने शुरू कर दिए हैं. पी. राममूर्ति ने संकेत किया कि हाल ही के हमलों में जीवन बीमा कर्मचारियों सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों, रेल मजदूरों व सरकारी कर्मचारियों पर हमले व वहशियाना गोलीबारी, किसानों के आंदोलन को दबाना, न्याय-पालिका पर अंकुश और देश में वामपंथी तथा जनवादी सरकारों को बर्दाश्त न करना आदि सभी तथ्य इस का सबूत हैं कि देश में अधिनायकवाद की तेजी से पुनरावृत्ति हो रही है. राममूर्ति ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि सम्मेलन द्वारा बनाया गया कार्यक्रम सभी संबंद्धताओं के मजदूरों के सभी हिस्सों में विस्तार से समझाया जाए और इसे लोकप्रिय बनाया जाए ताकि इसे प्रभावशाली रूप से लागू कर सकें.

## क्रमबद्ध कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में क्रमबद्ध लंबे संघर्ष का आह्वान किया गया है जिसमें तीन महीनों के अन्दर राज्य क्षेत्र स्तर के सम्मेलत आयोजित करना, अभियान समिति की तरह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व अन्य संगठनों की इकाइयों की राज्य समितियों का निर्माण करना, एक दिन का प्रतिरोध व मांग दिवस मनाना, शीत-कालीन अधिवेशन में संसद पर कूच तथा सभी क्षेत्रों के सभी उद्योगों में एक दिन की हड़ताल आयोजित करना शामिल हैं.

शांति पटेल (एच. एम. एस.), जतीन चक्रवर्ती (यू. टी. यू. सी.), जे. एस. दारा (इंटक), प्रीतीश चंद्र (यू. टी. यू. सी. एल. एस.) और अमर चक्रवर्ती (टी. यू. सी. सी.) ने प्रस्ताव का समर्थन किया.

जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों से बोले वे थे— समर मुखर्जी (सीटू), रामनरेश सिंह (बी. एम. एस.), सामंतराय (एच. एम. एस.), के. एल. महेंद्र (एटक), एस. के व्यास (केंद्रीय सरकार कर्मचारी), सुकोमल सेन (राज्य सरकार कर्मचारी), सरोज चौधरी (एल. आई. सी.), सैमुएल आगस्टाइन (डिफेंस), एम. के. पंधे (कोल), एम. एम. लारेंस (वाटर ट्रांसपोर्ट), आर. के गर्ग (रेलवे), एस. के. धर (लोकोरनिंग स्टाफ), के. के. थेकेडथ (यूनिवर्सिटी और कालेज प्राध्यापक), मुहम्मद इस्माइल (रोड ट्रांसपोर्ट), एस. डब्ल्यू ढावे (एग्री-कल्चर लेबर), के. ए. राजन (विद्युत), नरेश दास (बैंक), और धनी राम खोसला (प्लांटेशन), सम्मेलन में कुल मिलाकर 55 व्यक्ति बोले.

बंगलोर स्थित पब्लिक सेक्टर यूनियनों के नेता माइकल फर्नांडीज, एम. एस. कृष्णन (ज्वाइंट एक्शन फ्रंट), एस. सूर्यनारायण राव (सीटू) और प्रभाकर घाटे (बी. एम. एस) ने सम्मेलन का स्वागत किया और केंद्रीय सरकार द्वारा पिछले वादों से मुकर जाने पर बोले.

वादविवाद का उत्तर देते हुए पी. राममूर्ति ने वक्ताओं द्वारा कुछ दिए गए सुझावों का स्वागत किया. शिवाजी पार्क में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई जिसको पी. राममूर्ति, इंद्रजीत गुप्ता, डी. डी. वशिष्ट, डी. थेंगड़ी और जातीन चक्रवर्ती ने संबोधित किया.

सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव को हम नीचे छाप रहे हैं.

# प्रस्ताव

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब समूचे देश का मजदूर वर्ग दशाब्दियों के जुझारू संघर्षों और बहादुराना बलिदानों से प्राप्त किए गए जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा वेतन व अन्य भत्तों पर चहुमुखी हमलों का सामना कर रहा है.

## आसमान छूती कीमतें

समूची कामकाजी जनता बढ़ती कीमतों तथा बढ़ती बेरोजगारी के बोझ से धस रही है.

1980 के लोक सभा चुनावों के दौरान किए गए ऊंचे वायदों के बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कीमत-रेखा को नियंत्रित रखने में बुरी तरह से नाकामयाब रही है. थोक मूल्य सूचकांक में मार्च 1981 के बीच लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अभी यह इसी तरह से बढ़ रही है और यह खासतौर से रिटेल की कीमतों में है. रोजाना की जीवनोपयोगी चीजें जैसे चीनी, दालें, खाद्य तेल, खाद्यान्न, कपड़ा, मिट्टी का तेल, घरेलू कोयला, साबुन, आदि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं.

आसमान छूती कीमत सरकार की नीतियों के कारण और ऊपर जा रही है क्योंकि सरकार कामकाजी जनता पर ज्यादा से ज्यादा बोझ लाद रही है जबकि यह पैसे व संपत्ति वाले वर्ग की खुशामद करती है.

सरकार के अप्रत्यक्ष करों में बड़ा भाग जरूरी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी का है. घाटे का बजट साल दर साल बढ़ रहा है. कोयले, इस्पात, पैट्रोल, रेल भाड़े और डाकखर्च, जिनके दामों का सरकार नियंत्रण करती है, प्रसाधन जुटाने के नाम पर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. उद्योगपतियों, सट्टाबाजारियों व कालाबाजारियों को भारी मात्रा में काला धन हड़प जाने की छूट है और वे इसका इस्तेमाल जमाखोरी व मुनाफाखोरी करके बाजार पर अपना नियंत्रण करने में करते हैं. बीयरर बांड योजना इन समाज विरोधी ताकतों को हाल में दी गई छूट है.

इजारेदारों और दूसरे शोषक वर्गों की सुविधाओं तथा मुनाफों पर चोट करके आर्थिक फर्क कम करने के लिए कदम उठाने की बजाए, सरकार आर्थिक शक्ति के और भी केंद्रीकरण के लिए जानबूझकर छूट दे रही हैं.

## वास्तविक वेतन में कमी

इसके बिल्कुल विपरीत सरकार आक्रामक है और वेतन ढांचे के 'रेशनलाइजेशन' की बात कर रही है जिसका मतलब है बेहतर वेतनों को नीचे के स्तर पर ले आना, जबकि कई क्षेत्रों में मौजूद, खासतौर से खेत व 'न्यूनतम वेतन' श्रेणी में, दर्दभरे कम वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही नही की गई है. संगठित उद्योग में मजदूर को डराया धमकाया जा रहा है कि जबतक वह ज्यादा कार्य-भार मंजूर नही करता है उसे ऊंचे वेतनों की मांग नही करनी चाहिए. और 'मुद्रास्फीति' को नियंत्रित करने के नाम पर महंगाई भत्ते व बोनस जैसी राशियों को कम या खत्म किया जा रहा है.

वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एंटरप्राइजेज के ब्यूरो ने सार्वजनिक उद्योग के प्रबंधकों को एक निदेश जारी किया है जिसने मजदूरों पर एक तरह से वेतन जाम थोप दिया हैं. जाहिर है कि निजी क्षेत्र के मजदूरों को भी नहीं बख्शा गया है. उनके ऊपर रथ कमेटी की सिफारिशों के खुल्लमखुल्ला ताक पर रख कर सरकार द्वारा बनाए गए धोखे भरे जीवन मूल्य सूचकांक थोपे जा रहे हैं. कीमतों में हर वृद्धि से मजदूरों के वास्तविक वेतन में और आगे गिरावट आ जाती है.

## जबरदस्त हमले

ठेका और स्थानांतरित मजदूरों की हालत, कामगार महिलाओं बच्चे श्रमिकों की हालत का वर्णन ही नही किया जा सकता.

लाभकारी दामों के लिए किसानों के संघर्षों और बेहतर वेतनों के लिए खेतमजदूरों के संघर्षों को बुरी तरह से दबाया जा रहा है.

यह देखकर कि मेहनतकश जनता में असंतोष तेजी से फैल रहा हैं और उनके प्रतिरोध की लहर लगातार आगे

बढ़ रही है, सरकार व मालिकान ने ट्रेड यूनियन अधिकारों और संघर्षों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बड़ी बेशर्मी के साथ ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं और हड़ताली मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है हालांकि ऐसा न करने के अनेक वायदे किये गए हैं. कांग्रेस (इ) द्वारा शासित एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में हड़तालों पर रोक लगाते हुए और उन्हें 'गैरकानूनी' घोषित करते हुए नए कानून बनाए जा रहे हैं. एक दम बर्खास्त कर देना, चार्जशीट देना, मुअत्तिल करना, तबादला करना, जबरदस्ती रिटायर कर देना और यहां तक कि ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को इलाके से बाहर निकाल देना रोजमर्रा की बात हो गई है.

सैंकड़ों को गिरफ्तार किया जाता है और फौजदारी के मनगढंत मामलों में फसा दिया जाता है, मालिकान के भाड़े के गुंडे ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं पर शारीरिक हमले करते हैं, उन्हें घायल करते हैं व यहां तक कि उनकी हत्या भी कर देते हैं और यही नही हड़ताली मजदूरों की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, और इन सबके प्रति पुलिस अंधी बनी रहती है.

गोलीबारी और लाठीचार्ज तो रोज ही होता है जिससे सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों तक को भी नही बख्शा गया है.

बिना किसी गलती के ये सब घटनाएं यह साबित करती हैं कि सरकार ने समझौते और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को तहस नहस करने का और मनमानी शर्तें और वेतन कमचारियों पर थोपने का फैसला कर लिया है. जीवन बीमा और आम बीमा में संघर्षों से बंगलोर स्थित सार्वजनिक उद्योगों में मजदूरों के लंबे संघर्ष के दौरान सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने से भी नही हिचकने और मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए चार यूनिटों में तालाबंदी करने से भी नही हिचकने से यही सबक मिलता है.

## कांग्रेस (इ) यूनियनों की हिमायत

ट्रेड यूनियनों की मान्यता के सवाल को सरकार जानबूझकर लटका रही है हालांकि इंदिरा कांग्रेस की इंटक, जिसकी प्रबंधक हिमायत करते हैं, को छोड़कर बाकी सभी ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि इसका फैसला मजदूरों द्वारा गुप्त मतदान के जनवादी तरीके द्वारा किया जाए.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बुनियादी कनवेंशने जैसे 'संगठन की स्वतंत्रता' और 'सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार' और अन्य अभी तक स्वीकृत नही की गई हैं

'उद्योग' की परिभाषा को इसमें शिक्षा संस्थानों व हस्पतालों के कर्मचारियों को शामिल करके बृहत्तर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी तक लागू नही किया गया है. इसके विपरीत युनिवर्सिटी और कालेज के अध्यापकों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिशें की जा रही हैं.

सरकार की श्रम-संबंध नीति कांग्रेस (इ) की यूनियनों की भारी समर्थक हैं हालांकि ऐसा वहां पर भी है जहां इन यूनियनों का मजदूरों का बहुमत बिलकुल भी प्राप्त नहीं है. अन्य ट्रेड यूनियनों से परामर्श केवल दिखावा मात्र है जैसा कि, उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए मजदूरों के प्रतिनिधि के चयन से प्रतीत होता है.

## भारी मत्हव

यह सम्मेलन इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करता है कि प्रतिक्रियावादी निहित स्वार्थों द्वारा मजदूरों को जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र, आदि के आधार पर विभाजित करने और मजदूर वर्ग के हिस्सों में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं ताकि इसकी एकता अस्त व्यस्त व कमजोर हो जाए और इसका ध्यान गलत मार्ग पर मोड़ा जा सके. इसलिए यह जरूरी है कि ट्रेड यूनयनें अपनी सतर्कता और गतिविधितां तेज करें और मजदूर वर्ग की एकता की रक्षा व इसे और मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करे नही तो ट्रेड यूनियन आंदोलन बरकरार नही रह सकता.

यह सम्मेलन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के लाखों मजदूरों का समान रूप से हार्दिक अभिनंदन करता है. इन मजदूरों ने पिछले साल काम व जीवनयापन के हालात की रक्षा और अपने जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों को बचाने के लिए बहादुराना संघर्ष चलाए हैं.

अनुभव यह दर्शाता है कि मजदूरों के विभिन्न वर्गों के पृथक संघर्षों को सरकार, मालिकान और राज्य मशीनरी की सांठगांठ से आमतौर पर दबा दिए जाते हैं. इसलिए यह भारी महत्व की बात हैं कि मजदूरवर्ग कीमत वृद्धि तथा सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी एकजुट आंदोलन की तैयारी करे.

पिछले सभी श्रम आंदोलनों के लाभों को खत्म करने की सरकार की कोशिशों से उत्पन्न चुनौती का सामना संगठित मजदूर वर्ग की एकजुट शक्ति को गंभीरता के साथ अनिवार्य तौर पर करना है.

## मांगें

यह सम्मेलन भारत के समूचे मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वह कीमत वृद्धि के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट हों और निम्न मांगों के लिए जोर डाले :

1. सभी जरूरी चीजों की बिक्री जैसे खाद्यान, खद्य तेल, कपड़ा, चीनी आदि घटी दारों पर लोकप्रिय समितियों के निरीक्षण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों से की जाए और उन चीजों की पर्याप्त और लगातार सप्लाई की गारंटी दी जाए.

2. किसानों को लाभकारी दाम व खेतिहर मजदूरों को बेहतर वेतन.

3. काला बाजारियों, जमाखोरों, सट्टाबाजारियों और उनको पनाह देने वाले आंदोलन में ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि वे उपभोक्ताओं और मेहनतकशों के अन्य हिस्सों

का भी सक्रिय समर्थन तथा सहयोग हासिल करे.

यह सम्मेलन मजदूर वर्ग का एक बार फिर आह्वान करता है कि वह निम्न आर्थिक मांगों और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए एकजुट हो :

1. पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित तरीकों के आधार पर जरूरत के मुताबिक न्यूनतम वेतन;
2. महंगाई के आंकड़ों में वृद्धि की पूरी भरपाई. बी. पी. ई द्वारा मनमाने ढंग से तय मूल्य सूचकांक (1960 आधार) में प्रति बिंदु बढोत्तरी पर एक रुपया तीस पैसे की सीमा को हटाना;
3. बोनस की अदायगी कानून में संशोधन जिसमें बिना किसी सीमा और पूर्वशर्त के सभी मजदूरों को बोनस का प्रावधान हो;
4. छटनी और कलोजर पर प्रतिबंध. बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया जाना;
5. मजदूरों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ विक्टिमाइजेशन के सभी कदम वापस लिए जाएं;
6. महंगाई के आंकड़ों में घोखाधड़ी को खत्म किया जाए.
7. गुप्त मतदान के द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी जाए.
8. बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी;
9. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व अन्य दमनकारी कदमों को वापस लिया जाए.

**कार्यक्रम**

इस लिए यह सम्मेलन आह्वान करता है कि आने वाले तीन महीनों के अंदर समूचे देश में राज्य या क्षेत्र के आधार पर इसी प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाएं ताकि इस सम्मेलन में प्रकाश में लाए गए मुख्य मुद्दों को मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों में लोकप्रिय किया जा सके. इसके लिए इसी प्रकार की राज्य अभियान समितियां बनाई जाएं.

मजदूरों में लगातार बढ़ते प्रभाव के साथ लंबे और लगातार आंदोलन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन यह प्रस्तावित करता है कि राज्यव्यापी सम्मेलन आगे की कार्यवाही के साफ नजरिये से आयोजित किए जाएं जिसमें निम्न भी शामिल हैं.

1. अखिल भारतीय प्रतिरोध व मांग दिवस मनाना;
2. भारी तादाद में मजदूरों का संसद के लिए कूच; और
3. उद्योग के हर क्षेत्र में देशव्यापी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल.

यह सम्मेलन राष्ट्रीय अभियान समिति को यह अधिकार देता है कि वह उपरोक्त व अन्य जरूरी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त तारीखें तय करे ताकि मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश हिस्सों को बहुत ही प्रभावखाली ढंग से एकजुट किया जा सके.

मजदूर वर्ग और गांवों की मेहनतकश जनता की एकजुट शक्ति इतनी जबरदस्त ताकत होगी कि यह सरकार की मजदूरवर्ग विरोधी, जन विरोधी, इजारेदार परस्त, बहुराष्ट्रीय कंपनी परस्त नीतियों में परिवर्तन ला सकेगी. □

## बिहार ग्लास और पोटरीज़ कर्मचारियों का सम्मेलन

बिहार ग्लास और पोटरीज़ कामगार यूनियन (सीटू) का तीसरा सम्मेलन मधुपुर में 9 और 10 मई को हुआ. अब्दुल हकीम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया.

यूनियनों के महासचिव नूर इमान ने अपनी रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट पर बहस में करीब दस प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा मांग की है कि ग्लास और पोटरीज़ कर्मचारियों के वेतनमानों को शीघ्र ही फिर से तय किया जाए और 'न्यूनतम वेतन' कमेटी का निर्माण किया जाए और उसमें सीटू का प्रतिनिधित्व हो. एक दूसरे प्रस्ताव में मांग की गई है कि आवश्यक बस्तुओं को कंट्रोल रेट की दुकानों पर घटी दरों पर बेचा जाए. अन्य प्रस्ताव में सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई तथा लोकोरनिंग स्टाफ, बीमा कर्मचारियों आदि पर हमले की निंदा की गई.

सम्मेलन ने चंडी प्रसाद अध्यक्ष, अब्दुल हकीम कार्यकारी अध्यक्ष और नूर इमाम महासचिव सहित 25 सदस्यों की एक नई कार्यकारी समिति चुनी. □

## स्पीड क्राफ्ट्स कर्मचारियों पर हमले

पटना में स्पीड क्राफ्ट्स के कर्मचारियों ने फैक्ट्री में कुछ समय से गैर कानूनी ढंग से तालेबंदी के विरुद्ध संघर्ष किया. श्रम विभाग के प्रयत्नों के बावजूद प्रबंधकों ने मजदूरों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया था.

21 मई को सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे शांतिपूर्ण कर्मचारियों पर हमला किया उनके घर जला दिए. बिहार, सीटू के महासचिव चंडी प्रसाद ने 22 मई को एक बयान में कर्मचारियों पर हमले तथा प्रबंधक समर्थक नीतियों के लिए अधिकारियों की आलोचना करते हुए उच्च अधिकारियों से अपील की कि औद्योगिक झगड़ों में पुलिस हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए तथा मांग की कि इंजीनियरिंग वेतन बोर्ड के निर्णय को लागू करवाने के लिए श्रम-विभाग प्रबंधकों को मजबूर करे □


## सीटू की मासिक पत्रिकाओं को पढ़िए

## दि वर्किंग क्लास

*(अंग्रेजी में)*

## सीटू मजदूर

*(हिंदी में)*

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

**सीटू कार्यालय**
**6, तालकटोरा रोड,**
**नई दिल्ली 110001**

## अखिल भारतीय हड़ताल पर . . .

[मुख्य पृष्ठ से आगे]

प्रवृत्तियों के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष का एक हिस्सा है. इन्हें देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति से अलग नही किया जा सकता है.

कांग्रेस (इ) सरकार न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव का चाटुकार हथियार बनाने के लिए कटिबद्ध है. यह हमला लगातर तेज किया जा रहा है. जीवन बीमा कर्मचारियों को बोनस दिए जाने ने न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बीच संग्राम का फैसला नही किया है. यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन इन हमलों को धराशयी करने और नाकारा बनाने के लिए अपना पूरा जोर नही लगाता है तो ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई में यह यह मात खा जाएगा. इसका सबक यही है कि अधिनायकवाद विरोधी सभी ताकतों से सहयोग किया जाए.

ट्रेड यूनियन आंदोलन को चाहिए की वह राष्ट्रपति प्रणाली के खतरों को नोट करे जिसे कांग्रेस (इ) पार्टी देश पर थोपने की कोशिश कर रही है. राष्ट्रपति प्रणाली का आह्वान एक पार्टी शासन के लिए व व्यक्तिगत तानाशाही के लिए आह्वान के सिवाए कुछ नहीं है और मजदूर वर्ग को पूरी चेतावनी दी जानी चाहिए तथा इस अधिनायकवादी षड़यंत्र के अन्य जनवादी ताकतों से मिलकर काम करने के लिए इसका आह्वान किया जाना चाहिए. जनवादी और अधिनायकवादी ताकतों के बीच लड़ाई में उतार-चढ़ाव आते हैं तथा इसकी लगातार सफलता के लिए मजदूरों व ट्रेड यूनियन आंदोलन को सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

### अधिनायकवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में परास्त

सम्मेलन के एक सप्ताह पहले अधिनायकवादी पार्टी और इसके सहयोगियों को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है. म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंका गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाममोर्चे की 87 म्यूनिसिपल कमेटियों में से 68 में शानदार जीत हुई. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मजदूर वर्ग और जनवादी जनता चट्टान की तरह वामपंथी मोर्चे के साथ रही.

विधान सभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस (इ) को इससे बड़ी हार खानी पड़ी. वाम मोर्चा सरकार की नीतियों के कारण ही जनवादी ताकतों और मजदूर वर्ग की जीत हुई है क्योंकि वाम मोर्चा सरकार ने सभी जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों की सख्ती से रक्षा की और किसानों का साथ दिया.

दूसरे राज्यों में सभी उपचुनावों में विरोधी पार्टियों की हार हुई है, इसका एक कारण यह भी है कि निर्लज्ज कांग्रेस (इ) प्रशासन ने भारी धोखाधड़ी की. लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पार्टिया मजदूरों को अपने साथ नहीं ले चल सकी. क्योंकि इनके पास वैकल्पिक नीतियां नहीं थी.

### अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करो

मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन अधिकारों व जीवनयापन के बेहतर हालात के लिए संघर्ष के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज नही कर सकता. इसकी एकजुट आवाज न्यायपालिका पर हमलों और राष्ट्रपति प्रणाली को थोपने के खिलाफ उठनी चाहिए. इसे बेहिचक वाम मोर्चा सरकारों द्वारा कांग्रेस (इ) के खिलाफ संघर्ष की प्रशंसा करनी चाहिए और उनके बढ़ते प्रभाव का स्वागत करना चाहिए. सम्मेलनों और एक दिन की हड़ताल के लिए तैयारी के दौरान इसे अपने अनुयायियों के अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष को और आगे बढ़ाने में सक्रिय तौर पर भाग लेने का आश्वासन देना चाहिए. □

---

## कोल्हापुर में श्रमिक महिला सम्मेलन

महाराष्ट्र श्रमिक महिला संघ का दूसरा सम्मेलन 29-30 मई को कोल्हापुर में संपन्न हुआ. बीड़ी, खेत व औद्योगिक मजदूरों, बैंक व बीमा कर्मचारियों, अध्यापकों और कामकाजी जनता के अन्य हिस्सों के 500 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया.

एक आदिवासी महिला और थाने जिला में तालासारी पंचायत को सरपंच, हेमलता कोम ने झंडा फहराया. स्वागत समिति की अध्यक्ष सुशीला शेडवाले ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया. सीटू की वर्किंग कमेटी की सदस्य अहिल्या रंगनेकर ने अध्यक्षता की.

प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अहिल्या रंगनेकर ने महिलाओं के सभी हिस्सों पर बढ़ते हमलों जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ और समाज के हिस्से द्वारा दहेज के कारण तंग किया जाना और कभी कभी पुलिस द्वारा भी तंग किए जाने के खिलाफ उन्हें सचेत किया. समाज में महिलाओं के स्थान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि पति या मां-बाप के साथ रहते महिलाएं परिवार में हाथ बटाती हैं लेकिन उन्हें घर के आर्थिक मामलों में कुछ कहने का कोई हक नही है. हमारे समाज ने उनको इस तरह पीछे धकेल दिया है कि वे संविधान के अनुसार अधिकारों की भी मांग नहीं कर सकती. मौजूदा हालात की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हम इंदिरा गांधी से कोई उम्मीद नही कर सकते. संविधान में जो भी रक्षा-साधन दिए गए हैं वे बिलकुल नाकाफी हैं और कानूनों में भी ढेर सारी कमियां हैं. उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर संघर्ष करें नही तो ऐसे समाज में महिलाओं का इज्जत के साथ बसर

[शेष पृष्ठ ग्यारह पर]

# आसाम सीटू की गतिविधियां तेज

'विदेशी-विरोधी' कट्टरपंथी आंदोलनकारियों के घातक विरोध के बावजूद आसाम सीटू ने धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर वर्ग को एकजुट करने का आंदोलन तेज कर दिया है.

अप्रैल और मई के महीनों में सीटू यूनियनों ने संघर्ष काफी आगे बढ़ाए हैं जिनके फलस्वरूप प्लाईवुड, छाता निर्माण, ब्रह्मपुत्र जूट मिल, मेघालय जूट मिल के मजदूरों के सफल वेतन समझौते हुए हैं. दुकानों और संस्थानों तथा सड़क निर्माण में न्यूनतम वेतनों पर वेतनबोर्ड के त्रिपक्षीय समझौते हुए. प्लाईवुड उद्योग के 9000 मजदूरों ने सीटू के आह्वान पर एक दिन की हड़ताल की जिसने मालिकान को कलोजर के दौरान का वेतन देने के लिए मजबूर कर दिया.

आसाम में इंजीनियरिंग उद्योग में सीटू आगे बढ़ी हैं और सीटू की सभी यूनियनों की एक तालमेल समिति बन गई है जिसने नए त्रिपक्षीय समझौते के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है क्योंकि पिछला समझौता काफी पहले खत्म हो गया है.

सीटू यूनियन ने आसाम में जीवन बीमा कर्मचारियों को उनकी हड़ताल के दौरान समर्थन दिया. पृथकतावादी ताकतों के विरोध के बावजूद जीवन बीमा कर्मचारियों के समर्थन में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 अप्रैल को अखिल भारतीय एकजुटता दिवस आयोजित करने के लिए सीटू ने गोहाटी में भारी मात्रा में मजदूरों को एकत्रित किया.

## मई दिवस

इस साल आसाम में मई दिवस की रैलियों ने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए. इस बार मई दिवस के दिन लाल झंडे न केवल बड़े और छोटे शहरों में लहराए बल्कि गांवों में भी फहराए गए जहां मजदूरों, छात्रों और युवकों ने बड़े उत्साह से असंख्य रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए जिनमें से कुछ तो मजदूर स्वर्ग की विशाल रैलियां साबित हुई. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रैली गोहाटी में आयोजित की गई जहां सीटू ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और केंद्रीय व राज्य फेडरेशनों सहित अन्य संगठनों को रैली में भाग लेने के लिए एकजुट करने के लिए पहलकदमी की. बी. एम. एस. ने भी जो अब तक मई दिवस में भाग नही लेती थी इसबार सांकेतिक तौर पर रैली में भाग लिया. लेकिन, इंटक ने भाग नही लिया. सीटू की आसाम राज्य कमेटी के महासचिव अमल घोष दस्तीदार रैली में मुख्य वक्ता थे. उन्होंने मई दिवस के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला और कट्टरपंथी व पृथकतावादी ताकतों, जिन्होंने मजदूर वर्ग को विभाजित करने की नापाक कोशिश की, के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. सीटू और अन्य ट्रेड यूनियनों के अनुरोध पर आसाम की सरकार को मई दिवस के दिन सवेतन छूट्टी की घोषणा करनी पड़ी. जिला अधिकारियों ने भी मई दिवस के दिन रैलियां आयोजित करने की इजाजत दे दी.

सीटू के झंडे के नीचे चाय बागान मजदूरों द्वारा मई दिवस रैलियों में भारी मात्रा में भाग लिया जाना एक महत्वपूर्ण बात थी. चाए-बागान मजदूरों द्वारा विभिन्न स्थानों पर अनेक बड़ी रैलियों और जुलूसों ने मई दिवस की कार्यवाहियों में और भी रंग ला दिया.

## चाय-बागान मजदूरों पर भारी दमन

आसाम के चाए बागान मजदूरों में सीटू के विकास ने इंटक और बागान मालिकान में खलबली मचा दी है. सीटू यूनियनों के मजदूरों पर बागानमालिकान ने पुलिस के साथ सांठगांठ करके जबरदस्त दमन ढाना शुरू कर दिया है और कृष्णाकली चाए एस्टेट (गोआलपाड़ा जिला) के हस्पताल को पुलिस छावनी बना दिया गया है.

15 मई की रात को कृष्णाकली चाए एस्टेट के दो मजदूरों को मनगढंत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. उनके सारे कपड़े उतार दिए गए और तब तक पीटा गया जब तक वे बेहोश नहीं हो गए. बाद में पुलिस थाने में उन्हें हथकड़ी पहना दी गई. बड़ालाइन में पुलिस ने इस कदर आतंक फैलाया कि पुरुष मजदूरों को अपनी जीवन रक्षा के लिए घरों से भागना पड़ा. इस असामान्य स्थिति का फायदा उठाते हुए पुलिस ने उस दिन श्रीमती फुंगी के साथ बलात्कार किया. जब उसकी सास ने इसका विरोध किया तो उस पर हमला बोल दिया गया. बागान मैनेजर, भाड़े के गुंडों और पुलिस असहाय और पीड़ित महिला मजदूरों पर घातक हमले कर रहे हैं.

10 जून की रात को, प्रबंधकों के गुंडों ने अखिल भारतीय चा-मजदूर यूनियन (सीटू) की कृष्णाकली चाए एस्टेट ब्रांच के अध्यक्ष निहाल उरंग के घर में आग लगा दी और उसके सारे सामान को जलाकर राख कर दिया. पहले भी 25 मार्च को उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस उसके घर में घुस गई थी, उसकी पत्नि को गंदी भाषा में गालियां दी तथा उसके साथ छेड़छाड़ की थी.

इसी तरह के हमले चापुड़, डिल्ली और दूसरी चाए एस्टेटों में हो रहे हैं. ये हमले मजदूरों में आतंक फैलाने और उन पर दमन करने के लिए हो रहे हैं.

कितनी शर्म की बात है कि इन हमलों के शिकार चाए बागान के आदिवासी और जनजाति मजदूर हैं, लेकिन तैमूर सरकार ने आसाम में अल्पसंख्यकों की रक्षा के बजाए राज्य पुलिस ब्रिटिश और भारतीय दोनों चाए बागान मालिकान के हाथ समर्पित कर दी है.

सीटू के महासचिव पी राममूर्ति, एम. पी., ने श्रीमती तैमूर के नाम एक पत्र में इन बर्बर हमलों का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि "राज्य में सरकार की मुखिया होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है कि नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता की गारंटी मिले. उन्होंने अनुरोध किया कि "आप तुरंत हस्तक्षेप कर इस अमानवीय दमन को बंद कराएं".

[शेष पृष्ठ बारह पर]

# भारत में संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का उल्लंघन

इन समाचारों का खंडन करते हुए कि भारत का नाम काली सूची पर रख दिया गया है, भारत सरकार ने एक प्रैस बयान में दावा किया कि "दुनिया में किसी भी दूसरे देश की तुलना में भारत का इस संबंध में सबसे अच्छा रिकार्ड है."

नई दिल्ली में 19 जून को आयोजित एक सवांददाता सम्मेलन में सीटू के महासचिव पी राममूर्ति ने कहा.

"कई शिकायतों के मामलों में जिसमें भारत से संबंधित शिकायत न० 995 (बोड्र रोड्स आर्गेनाइजेशन) शामिल है जब बार-बार पत्र भेजने पर भी विभिन्न सरकारों से कोई जबाब नही मिला तो संगठन की स्वतंतता पर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पिछली बैठक में पेश की गई अपनी नवीनतम 208वी रिपोर्ट में कहा है कि 'इस संबंध में समिति यह कहना चाहती है कि गवर्निंग बाडी द्वारा स्वीकृत इसकी 177 वीं रिपोर्ट के 17वें पैरा में निर्धारित कार्यविधि के नियमों के मुताबिक, यह समिति, अपने आगामी अधिवेशन में इस बारे में उस तारीख तक सरकार की प्रतिक्रिया के न पहुंचने पर भी एक रिपोर्ट पेश करेगी'. यह वह मामला था जिसमें सीटू ने संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को की थी. यह तथ्य कि बार बार पत्र भेजने के बाद भी सरकार के पास कोई भी संतोषजनक जवाब भेजने के लिए नहीं था और यह तथ्य कि समिति को यह बात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को बतानी पड़ी तथा यह कहना पड़ा कि समिति को एक तरफा रिपोर्ट देनी पड़ेगी—ये सब सरकार के दावे को बेनकाब करते हैं.

भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस वास्तविकता से इंकार करे कि इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) की संगठन की स्वतंत्रता' 'सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार' पर कनवेंशन न० 87 तथा 98 को अभी तक अपनाया नहीं है. भारत सरकार द्वारा निर्मित कनवेंशनों पर एक समिति की पिछली बैठक में सीटू और मजदूरों के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह जोरदार मांग की थी कि भारत सरकार इन कनवेंशनों को तुरंत अपनाए.

सीटू इस बात की ओर इशारा करना चाहती है कि अतीत में ट्रेड यूनियन नेताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने, यूनियनों के दफ्तरों पर कब्जा करने और दूसरी प्रकार के दमन, 'संगठन की स्वतंत्रता' के अधिकार से इंकार करने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कई शिकायतें भेजी गई हैं और कई मामलों में आई. एल. ओ. की संगठन की स्वतंत्रता पर समिति ने अपनी अस्वीकृति दी है. जनवरी 1980 में जब से कांग्रेस (इ) सत्ता में आई है ट्रेड यूनियन अधिकारों, हड़ताल के अधिकार, संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं. मिसाल के तौर पर लोको रनिंग स्टाफ की पिछली हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को इस आधार पर बर्खास्त किया गया कि उनके पिता हड़ताल पर हैं. रेल मंत्री ने यह घोषणा की थी कि अगर ऐसे मामले उनके पास लाए गए तो वह उन्हें तुरंत ठीक कर देंगे. उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन आदेशों पर स्थगन आदेश जारी कर दिए. रेलवे बोर्ड खुशी से अदालतों में सार्वजनिक धन को बर्बाद कर रहा है. मंत्री ने उन अफसरान के खिलाफ क्या कदम उठाया है जो खुशी इस असभ्य मार्ग पर चलते हैं. यही बात उड़ीसा राज्य सरकार कर्मचारियों के संघर्ष के दौरान भी दोहराई गई जब हड़ताल के नेता के लड़के को पुलिस रात अंधेरे में उठा ले गई, उसे बुरी तरह से पीटा गया और 20 घंटों तक अपने कब्जे में बिना रोटी पानी के रखा. आसाम के गोआलपाड़ा जिले में कृष्णाकली और जापाड़ चाए बागान में मजदूरों को गिरफ्तार कर किया गया, उन्हें रस्सी से बांध कर जमीन पर पुलिस द्वारा लिटा दिया गया, और अफसरान ने उनके मुंह और सिर पर पेशाब किया. यूनियन अध्यक्ष निहाल उरंग का घर जला दिया गया. इससे पहले उसकी पत्नि को गालियां दी गई तथा तंग किया गया. क्या ये सरकार के या इसकी पुलिस बल के सभ्य काम है ?

समूचे देश में जो बर्बर दमन हो रहा है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती. हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज और गोलीकांड से पी डब्ल्यू डी कर्मचारी कत्ल कर दिए गए और घायल हो गए. 500 कर्मचारियों को केवल इसलिए सीधे-सीधे बर्खास्त कर दिया गया कि उन्होंने नौकरी सुरक्षा की मांग की थी. 7000 से भी ज्यादा लोकोरनिंग स्टाफ को इसलिए विक्टिमाइज किया गया कि उन्होंने 1974 में उनके साथ हुए समझौते को लागू न किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी. तालचेर में रेलवे कर्मियों के परिवारों की महिला सदस्यों पर हमले किए गए. समूचे हरयाणा में प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों और पुलिस की सांठगांठ है और वे सभी संघर्षों का दमन करते हैं. कांग्रेस (इ) द्वारा शासित कई राज्यो में अधिकारी हड़तालों का नेतृत्व करने वाली यूनियनों से समझौतावार्ता करने से इंकार करती हैं. ज्यादा से ज्यादा हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ राष्ट्रोय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है.

यूनियन बनाने पर विक्टिमाइज कर देना आज आम बात हो गई है. गोपीचन्द टैक्सटाइल मिल, हिसार, में पिछलो दो दशकों से कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं थी. जैसे ही सीटू ने यहां यूनियन बनाने के लिए कदम उठाए, प्रबंधको के भाड़े को गुंडों ने हरयाणा पुलिस से सांठगांठ करके मजदूरों पर गोलियां चलाई और उनको आतंकित किया. कोटा में आर एस ई बी प्रोजेक्ट के एक उप ठेकेदार ने 104 मजदूरों को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने कानून के तहत सरकार 34 निर्धारित न्यूनतम वेतन की मांग की थी. इसके खिलाफ सभी 1,500 मजदूरों ने काम रोक दिया. उप ठेकेदार ने आर एस ई बी और भेल से अपनी सारी धनराशि बटौरी और चलता बना. ये दो सार्वजनिक कंपनिया अब यह कहकर अपने वायदे से मुकर रही हैं कि ये मजदूर हमारे मजदूर नहीं हैं.

झूठे और मनगगढ़ंत आरोप जैसे कत्ल करने की साजिश ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ लगाये जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा समय तक जेल में बंद किया जा सके. सीटू मध्य प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष पी. के. मोइत्रा जो खुद एक प्रसिद्ध वकील हैं को अन्य के साथ जेल में रखा जा रहा है.

ऐसे मामलों की कतार बहुत लंबी है. यह जाहिर है कि सरकार का दावा सच को तोड़ने मरोड़ने और जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नही है. सीटू को पूरा विश्वास है कि सरकार के ये इरादे कभी सफल नहीं होंगे. □

## जूट मजदूरों ने देशव्यापी मांग दिवस मनाया

पिछली मार्च में नई दिल्ली में आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन की कार्यकारी कमेटी के बैठक के निर्णयों के अनुसार फेडरेशन के आह्वान पर 11 मई को जूट कर्मचारियों ने समूचे भारत में मांग दिवस मनाया. जब से आल इंडिया फेडरेशन का निर्माण हुआ है तब से जूट मजदूरों की समूचे भारत में यह पहली कार्यवाही है.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा में जूट मजदूरों की ट्रेड यूनियनों ने हजारों जूट मजदूरों के हस्ताक्षर करा कर जूट मिलो से संबंधित अधिकारियों को चार सूत्री मांग पत्र पेश किया. उस दिन अनेक रैलियां तथा सभाएं आयोजित की गई. संबंधित प्रबंधकों को भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा श्रममंत्री के नाम एम मांगपत्र पेश किया गया.

मांगपत्र में समूचे भारत के जूट कर्मचारियों ने मांग की कि (1) पश्चिम बंगाल के श्रममंत्री द्वारा जूट मजदूर के वेतनमान और ग्रेड के लिए की गई सिफारिशों के अनुसार समूचे देश में वेतनमान में एकरूपता हो. (2) समूचे देश में समान कार्यभार का नियम हो और 1972 से पूर्व की शर्तों के अनुसार पहले ही थोपे गए

[ शेष पृष्ठ ग्यारह पर ]

## सीटू द्वारा दुर्घटनाओं के लिए रेल मत्रालय की निंदा

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, एम. पी., ने 7 जून को निम्नलिखित वयान जारी किया:—

उत्तरपूर्वी रेलवे के बदलाघाट और घमराघाट स्टेशनों के बीच पुल के गिरने के कारण हुई दुर्घटना में 500 से अधिक व्यक्तियों की जानें चली जाने पर सीटू गहरा दुःख व्यक्त करती है और दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के शोकग्रस्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है.

सीटू रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय की आलोचना करती है क्योंकि इस दुर्घटना के लिए अकेले वे ही जिम्मेदार हैं. पिछली फरवरी में रेलवे बजट पर बहस के दौरान मैंने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि पिछले 15 वर्षों से रेल की पटरी, पुल और रोलिंग स्टाक की देखभाल की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रहा है. अर्थव्यस्था को चलाने के नाम पर इन सब विभागों में देखभाल करने वाले स्टाफ की घनी कमी के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है. भारी बोझ के साथ हाल ही के ट्रेन परिवर्तन ने स्थिति को और अधिक गंभीर बनाया है. यह दुर्घटना मेरी चेतावनी को सही ठहराती है.

सीटू मांग करती है कि रेलवे मंत्रालय को शोघ्र ही वर्तमान नीतियों को बदलना चाहिए और पुरानी रेल की पटरी, पुल और रोलिंग स्टाक तथा उनकी सही देखभाल के लिए फिर से तेज कार्यक्रम बनाए जाएं. यह केवल स्टाफ के काम के बौझ और काम के घंटों को घटा कर ही किया जा सकता है. सीटू सरकार को चेतावनी देती है कि जब तक यह ऐसा नहीं करती तब तक इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और बहुमूल्य मानवीय जीवन के नष्ट होने को कम नहीं किया जा सकता. अर्थव्यवस्था के पहले के बुनियादी अस्त-व्यस्त ढांचे को ये दुर्घटनाएं और खोखला बना देती हैं.

सीटू एक बार फिर चेतावनी देती है कि निर्दोषों को मुजरिम ठहरा कर धोखा देने से रेलवे की दुर्घटनाओं की अधिकता को कम नहीं किया जा सकता. □

# कानपुर होजियरी मजदूरों की अनिश्चित कालीन हड़ताल

टैक्सटाइल मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में कानपुर के होजियरी मजदूर, 500 रुपये न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता, वेतन-सहित और आकस्मिक अवकाश, 8 घंटे ड्यूटि, विक्टिमाइज किए गए मजदूरों की पुनः बहाली आदि मांगों के समर्थन में 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल पर जाने से पहले मजदूरों ने राज्य श्रम मंत्री के घर के सामने एक धरना आयोजित किया था.

हड़ताल की शुरूआत से ही मालिकान मजदूरों की लड़ाकू एकता को तोड़ने के लिए गुंडों का सहारा ले रहे हैं. 12 मई को मालिकान के कुछ पालतू गुंडों ने धरने पर बैठे हुए शांतिपूर्ण मजदूरों पर घातक हथियारों से हमला किया और अनेक को घायल किया. यूनियन के महासचिव रामेश्वर प्रसाद मिश्र सहित अनेक मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया.

पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ने करने पर तथा होजियरी मालिकान के मजदूर-विरोधी रवैये को मध्येनजर रखकर मिश्र ने अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल शुरू की और अन्य मजदूरों ने क्रमिक हड़ताल में भाग लिया. 30 मई को पुलिस ने आर. पी. मिश्र को गिरफ्तार किया जिससे मजदूरों में गहरा असंतोष फैल गया. इन कार्यवाहियों के बावजूद भी हड़ताली मजदूरों का उत्साह कायम है.

30 मई को एक बयान में यूनियन अध्यक्ष दौलत राम ने गुंडों द्वारा हमलों तथा पुलिस की दखलंदाजी की कड़ी आलोचना करते हुए मजदूरों की मांगों पर तुरंत समझौता करने की मांग की है. □

# बिहार के उद्योगों मे तालाबंदी की चाहत

बिहार सरकार ने 24 फरवरी को अचल महंगाई भत्ते के एक नये फार्मूले की घोषणा की जिसे कई मिल मालिकान ने लागू नहीं किया है. अनेक मालिकान ने तो इंजीनियरिंग वेज बोर्ड के फैसले को भी लागू नहीं किया है. यह समझा जाता है कि मिल मालिकान इसे लागू न होने देने के लिए मसले को कोर्ट में ले जाने के प्रयत्न कर रहे हैं.

बिहार सीटू के महासचिव चंडी प्रसाद ने 21 मई को एक बयान में मजदूरों को अपने जायज वेतन के खिलाफ मिल मालिकान द्वारा किए गए षड़यंत्रों का पर्दाफाश करने का आह्वान किया. □

# संक्षिप्त समाचार

**जे. के. सिंथेटिक्स मजदूर यूनियनः** यूनियन का वार्षिक सम्मेलन 24 मई को कोटा में आयोजित किया गया. यूनियन के महासचिव विजयशंकर झा ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे बातचीत के बाद अपनाया गया. इसमें फौरी मांगों तथा वर्तमान हालात पर कई प्रस्ताव अपनाए गए. कानफ्रेंस ने पी. एन. ढांढा को अध्यक्ष तथा विजयशंकर झा को महासचिव चुना.

**जयपुर में सीटू स्थापना दिवसः** 30 मई को समूचे जयपुर में गेट मीटिंग आयोजित करके सीटू स्थापना दिवस मनाया गया. वक्ताओं ने मीटिंगों में सीटू की उपलब्धियों और एकजुट आंदोलनों के जरिए हासिल किए गए अनुभवों पर प्रकाश डाला.

**इला भट्ट का निष्कासनः** आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन, जनवादी महिला समिति तथा कई माहला संगठनों के प्रतिनिधियों की 21 मई को नई दिल्ली में हुई एक बैठक ने अहमदाबाद की टैक्सटाइस लेबर एसोसिएशन के नेताओं की, सेल्फ एंप्लाईज वूमेंस एसोसिएयन को अपनी इमारत से निकाल बाहर करने तथा इसकी सचिव श्रीमती इला भट्ट को टी. एल. ए. की सदस्यता से निकालने की कड़ी आलोचना की. एक प्रस्ताव के जरिए बैठक ने श्रीमती भट्ट तथा एस ई डब्ल्यू ए के सदस्यों के साथ अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन के समर्थन में अपना बिरादराना संबंध घोषित किए.

**प्रधानमंत्री के बयान की आलोचनाः** दिल्ली की कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन ने 23 जून को एक बयान में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान की कड़ी आलोचना की जो एक गलत धारणा का समर्थन करता हैं. और यह न केवल एयरलाइंस की महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव करता हैं बल्कि उन्हें कामुकता का साधन भी मानता है. इसने प्रधानमंत्री से अपना बयान वापस लेने और इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के प्रबंधकों को महिलाओं के साथ भेदभाव करने तथा उनके लिंग के आधार पर शोषण करने के गलत तरीकों को खत्म करने के आदेश देने की मांग की.

**दिल्ली के होटल मजदूरः** गेलार्ड आइस क्रीम फैक्ट्री के मजदूरों ने मालिकान के मजदूर-विरोधी रवैये के खिलाफ 20 मई को हड़ताल की. जनरल मैनेजर द्वारा अपनी गलती कबूल करने के बाद ही हड़ताल को वापस लिया गया-

**म्युनिसिपल मजदूरों की कानफ्रेंसः** म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (सीटू) की 11 वीं कानफ्रेंस 24 अप्रैल को संपन्न हुई. दिल्ली सीटू के महासचिव, सांसद, सुशील भट्टाचार्य ने इसका उद्घाटन किया. महासचिव द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर बहस में 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कानफ्रेंस ने चाचा शादी राम को अध्यक्ष और बच्चन सिंह को महासचिव चुना.

**नायनार का छत्तीसगढ़ क्षेत्र का दौरा :** केरल की वाम तथा जनवादी मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री ई. के. नायनार ने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र का 28 और 29 मई को दौरा किया. उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक रैलियों को संबोधित किया और मजदूरों सहित विद्यार्थियों, युवकों ओर अन्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया. दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर तथा अन्य केंद्रों के मजदूरों में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् केरल में हुई उन्नति को देखकर बहुत जोश उत्पन्न हुआ. कांग्रेस (आइ) के गुंडों ने पुलिस के साथ मिलीभगत करके अनेक मीटिंगों को असफल करने के प्रयत्न किए. भिलाई

स्टील प्लांट के प्रबंधक एक ओर तो यह दर्शा रहे थे कि नायनार उनके अतिथि है और दूसरी तरफ उन्होंने जहां मीटिंग हो रही थी की बिजली कटवा दी.

**जयपुर के प्रिंटिंग मजदूर :** लगभग 500 प्रिंटिंग मजदूरों की 2 जून को जयपुर में एक बैठक हुई जिसमें शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया.

**कोयला श्रमिकों पर दमन :** भटगवां कोलियरी (डब्ल्यू सी एल, बिलासपुर, मध्यप्रदेश) के कोयला मजदूर हाल ही के महीनों में और खासतौर से मई और जून में मनमाने दमन का मुकाबला कर रहे हैं. इस दौरान 87 मजदूरों को अपने काम से निकाल दिया गया. इन मजदूरों की जमीन को कोलियारी ने छीन लिया था और अभी-तक उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है. इसके बदले में उन्हें रोजगार दिया गया था और वह भी इन प्रकार छीन लिया गया है. कोयला श्रमिक संघ (सीटू) सूरजपुर के एस डी ओ और अन्य अधिकारिगण से मिला. जब कोई कार्यवाही नही की गई तो मजदूरों ने 19 जून को सांकेतिक हड़ताल की. इस क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हैं.

**बिहार के ट्रांसपोर्ट मजदूर :** बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने मजदूरों की दुम्का डिपो में बसों की संख्या में वृद्धि, 240 दिनों की अवधि का काम पूरा करने वाले सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, वर्दी देना, अफिस पदाधिकारियों के विक्टिमाइजेशन का खात्मा आदि, जयज और न्यायसंगत मांगों पर गौर करने के बजाय यूनियन के नेताओं नित्यानंद तिवारी और राजा रघुनंदन को पटना के ट्रांसपोर्ट भवन के सामने 12 और 13 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया. बिहार सीटू के उपाध्यक्ष हरी कृष्ण और महासचिव चंडी प्रसाद ने 24 जून को एक बयान में मजदूरों की मांगों पर तुरंत समझौता करने की मांग की है.

**राजस्थान इलैक्ट्रिक यंत्र :** जयपुर स्थित मालवीयनगर के राजस्थान इलैक्ट्रिक इक्यूपमेंट के मजदूरों ने 9 मई से फिर से काम शुरू किया. मजदूर 11 अप्रैल से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर थे. मालिकान और स्माल स्केल लेबर यूनियन (सीटू) के मध्य 8 मई को एक समझौता हुआ जिससे मजदूरों को 52 रुपये वेतन वृद्धि, 7 दिन की आकस्मिक छुट्टी, त्यौहारों की 10 दिन की छुट्टी और दुगना ओवर टाइम आदि हासिल हुआ.

**एफ सी आई कर्मचारियों का संघर्ष:** कांडला स्टीवडोर्स एंड डाक वर्कर्स यूनियन की 5 जून को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में संघर्षरत कर्मचारियों की ओर से एफ सी आई मालिकान की मजदूर-विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की और कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द हल करने के लिए मालिकान पर जोर दिया. समिति ने कहा कि यदि तुरंत कोई हल नहीं निकाला गया तो क्षेत्र में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाएगा.

**हरिद्वार और ऋषिकेश के मजदूरों की बैठकें :** 'भेल', हरिद्वार और आइ डी-पी एल, ऋषिकेश के मजदूरों ने 4 और 5 मई को आम सभाएं आयोजित की. दिल्ली सीटू के महासचिव सांसद सुशील भट्टाचार्य ने इन बैठकों को संबोधित करते हुए सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों की आलोचना की और मजदूरों को अपने जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. □

## श्रमिक महिला

[पृष्ठ छः से आगे]

करना मुश्किल हो जएगा.

सम्मेलन का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बीड़ी और खेत मजदूरों की कुछ बिलकुल अनपढ़ महिलाओं ने अपने शोषण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ीं, जेल गई और संघर्षों में बहुत ही कठिनाइयां सही. लेकिन वे सिर्फ इतना जानती हैं कि उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना पडेगा. इसका प्रतिनिधियों पर काफी असर पड़ा.

सम्मेलन में कई प्रस्ताव अपनाए गए जिनमें महिलाओं पर जुल्म, महिलाओं की समस्याएं, शांन्तिपूर्ण सहअस्तित्व, कीमत वृद्धि झुग्गी-झोंपड़ी वालों की समस्याएं, आदि पर प्रस्ताव भी शामिल हैं. सम्मेलन में 15-सदस्यीय कार्यकारी समिति चुनी गयी जिसकी शेवांता राजगोरे अध्यक्ष और अहिल्या रंगनेकर महासचिव हैं. तीस मई को एक आम सभा आयोजित की गई जिसे अहिल्या रगनेकर, प्रभा सावंत, हेमलता कोम, सुभाषिनी अली, और अन्यों ने संबोधित किवा. □

## जूट मजदूर

[मध्य पृष्ठों से आगे]

कार्यभार को समाप्त किया जाए. (3) असम कोआपरेटिव जूट मिल्स, जे. के. जूट मिल और कानपुर जूट उद्योग के विक्टिमाइज किए गए मजदूर और नेताओं को दुबारा बहाल किया जाए और कांग्रेस (आई) के सहयोग से प्रथकतावादियों द्वारा असम के ट्रेड यूनियन दफ्तरों पर जबरन कब्जे को समाप्त किया जाए तथा ट्रेड यूनियन के कार्यों में उन द्वारा किसी भी प्रकार दखलंदाजी न होने देने की गारंटी दी जाय (4) सरकार जूट उत्पादकों के लिए और उत्पादकों से सीधे कच्चा जूट खरीदने के लिए सही मूल्य निर्धारित करे तथा विदेशी ट्रेड सहित जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए.

आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन की अध्यक्ष लक्ष्मी सहगल और महासचिव निरेन घोष एम. पी. ने साढ़े तीन लाख जूट कर्मचारियों को उनकी शानदार कार्यवाही के लिए बधाई दी. उन्होंने जूट मजदूरों को जूट मजदूरों और जूट उत्पादकों के हितों में समूचे देश में जुझारु संघर्ष द्वारा जोशीला अभियान शुरू का आह्वान किया. □

## चाए बागान मजदूरों का सम्मेलन

सीटू से संबंधित चाबागान मजदूर यूनियन पश्चिम बंगाल का सम्मेलन 4-6 जून को मालबाजार, जलपाईगुड़ी में हुआ. इसमें 300 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

सम्मेलन के उद्घाटन के समय यूनियन के अध्यक्ष सुबोध सेन ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया. संयुक्त महासचिव मानिक सान्याल द्वारा दी गई रिपोर्ट को बीरसेन कुजुर ने पढ़ा. इस पर बहस में 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

यूनियन के महासचिव परिमल मित्रा ने मूल्यवान बहस के लिए प्रतिनिधियों को बधाई दी और मजदूरों के प्रति केंद्रीय सरकार के रवैये की विस्तार से चर्चा की. सम्मेलन ने 21 सूत्री मांगपत्र को पेश किया.

खुले अधिवेशन को पश्चिम बंगाल के मंत्री परिमल मित्रा, ज्योति बोस, सुबोध सेन, मानिक सान्याल और अन्यों ने सबोधित किया. □

## आसाम सीटू के बढ़ते कदम

[पृष्ठ सात से आगे]

क्योंकि संगठन बनाने की स्वतंत्रता का बुनियादी अधिकार इसमें सम्मिलित है, पी. राममूर्ति ने जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम निम्नलिखित तार भेजा है :

"आसाम में चाए बागान में मजदूरों के संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है. मजदूरों के नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं. उनकी पत्नियों को तंग किया जा रहा है. पूरी शिकायत भेज रहे हैं. कृपया हस्तक्षेप कीजिए". □

## सीटू प्रकाशन प्रेस में

**कीमत वृद्धि और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभी उद्योगों में एक दिन की हड़ताल की तैयारियों पर**

*बंबई में 4 जून को आयोजित राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कनवेंशन के दस्तावेजों के साथ सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे का एक लेख*

**अनुमानित कीमत : 75 पैसे**

आर्डर इस पते पर भेजें :

**सीटू कार्यालय,**
**6, ताल कटोरा रोड,**
**नई दिल्ली-110001**

## सीटू का नवीनतम प्रकाशन

# बढ़ता दमन - शक्तिशाली संघर्ष !

**(हिंदी में)**

लेखक

**बी. टी. रणदिवे**

अध्यक्ष, सीटू

कीमत : 80 पैसे

**मिलने का पता :**

**सीटू कार्यालय,**
**6, तालकटोरा रोड,**
**नई दिल्ली-110001**

## महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

| राज्य/केंद्र | 1981 फर. | मार्च | अप्रैल |
|---|---|---|---|
| **बिहार** | | | |
| जमशेदपुर | 387 | 395 | 400 |
| झारिया | 391 | 393 | 397 |
| कोडर्मा | 421 | 422 | 427 |
| मोंघाइर | 452 | 446 | 438 |
| नोआमुंडी | 408 | 406 | 404 |
| **गुजरात** | | | |
| अहमदाबाद | 383 | 393 | 406 |
| भाव नगर | 414 | 418 | 438 |
| **हरियाणा** | | | |
| यमुना नगर | 449 | 457 | 467 |
| **जम्मू व काश्मीर** | | | |
| श्रीनगर | 420 | 428 | 449 |
| **मध्य प्रदेश** | | | |
| बालाघाट | 433 | 438 | 447 |
| भोपाल | 430 | 434 | 447 |
| ग्वालियर | 443 | 438 | 455 |
| इंदौर | 454 | 458 | 472 |
| **महाराष्ट्र** | | | |
| बंबई | 410 | 423 | 435 |
| नागपुर | 411 | 425 | 435 |
| शोलापुर | 440 | 444 | 472 |
| **पंजाब** | | | |
| अमृतसर | 426 | 427 | 442 |
| **राजस्थान** | | | |
| अजमेर | 450 | 444 | 449 |
| जयपुर | 464 | 456 | 446 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| कानपुर | 404 | 405 | 412 |
| सहारनपुर | 424 | 424 | 430 |
| वाराणसी | 483 | 490 | 484 |
| **पश्चिम बंगाल** | | | |
| आसन सोल | 432 | 429 | 435 |
| कलकत्ता | 384 | 385 | 379 |
| दार्जीलिंग | 334 | 344 | 347 |
| हावड़ा | 377 | 379 | 381 |
| जलपाइगुरी | 337 | 338 | 342 |
| रानीगंज | 406 | 404 | 412 |
| **दिल्ली** | 434 | 438 | 448 |
| **भारत** | 418 | 510 | 519 |

# जी डी आर में औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी

स्वतंत्र जर्मन ट्रेड यूनियंस के महासंघ की मासिक पत्रिका एफ डी जी बी रिव्यू ने देश में औद्योधिक दुर्घटनाओं के बारे में, जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के राज्य के श्रम और वेतन के राज्य सचिवालय में श्रम सुरक्षा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डाक्टर हार्स्ट रेहटांज का साक्षात्कार किया. उनका साक्षातकार इस प्रकार है:—

**क्या आप जनवादी जर्मन गणतंत्र (जी डी आर) में औद्योगिक दुर्घटनाओं के गिरते स्तर को दिखाने के लिए कुछ आंकडे पेश कर सकते हैं ?**

**रेहटांज :** अवश्य. यदि हम 1980 के पिछले अर्धवर्ष को लें तो हम पाएंगे कि 1979 में उसी अवधि में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या प्रति हजार रोजगार लोग 15.41 से कम होकर 14.32 हुई. यदि इससे भी लम्बी अवधि को लिया जाए तो यह संख्या विकसित और अधिक प्रत्यक्ष हो जाएगी. 1959 से 1979 तक के बीस वर्षों में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या 38.4 प्रतिशत तक गिरी और उसी दौरान जान हानि की दुर्घटनाओं की दर 56.2 प्रतिशत तक गिरी.

**इसके कारण कहां से पता लगाये जा सकते हैं ?**

**रेहटांज :** पहले पहल तो वे हमारे सामाजिक जीवन में आते हैं. और संक्षिप्त रूप में ये कारण हमारे देश में श्रम सुरक्षा के स्थान में निहित हैं. यह एक तथ्य है कि हमारे देश में मानव उद्धार प्रथम कर्त्तव्य है और हर कार्य, कामगार लोगों के उद्धार के लिये किया जा रहा है. हम उत्पादन और श्रम सुरक्षा को एक साथ लेकर चलते हैं. उत्पादन, श्रम-उत्पादन और श्रम-उत्पादकता का हर एक मापदंड, श्रम सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की जरूरतों को पूरा करता है. क्योंकि समाजवाद में श्रम सुरक्षा को रोजगार-दाता के एकमात्र उद्देश्य अर्थात मुनाफा कमाने से नीचे नही रखा जाता है और उत्पादन का प्रबंध और योजना जो लोगों की आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य रक्षा, जीवन में खुशी और श्रम से संतुष्टि आदि से जुड़ा हुआ है. श्रम सुरक्षा की आवश्यकताएं बार-बार उत्पादन की विधि के साथ एक अभिन्न एकता द्वारा ही पूरी की जाती हैं. औद्योगिक देशों में दुर्घटनाओं की ऊंची दरों से यह साफ-साफ पता चलता है कि श्रम सुरक्षा उतनी ही की जाती है जितनी कि मजदूर अपने और मालिक के बीच तीखे वर्ग-संघर्ष से निचोड़ पाता है और मालिक यह श्रम सुरक्षा वहां तक ही करते हैं जहां तक वे अपनी पूंजी के इस्तेमाल में लाभ की आवश्यकता महसूस करते हैं. लेकिन, समाजवाद में ऊंचे स्तर पर श्रम सुरक्षा समाज का मौलिक कार्य है. इसका यह भी अर्थ हुआ कि अधिकाधिक कार्यों को सुगठित किया जाता है और इसे नये सिरे स श्रम के वैज्ञानिक संगठन द्वारा सुगठित किया जाता है. 1980 के प्रथम अर्धवर्ष में ही 20 हजार कामगार लोगों की अस्वस्थ काम की शर्तों से छुटकारा पा लिया गया था.

**जी डी आर में ट्रेड यूनियनें श्रम सुरक्षा के नियंत्रण में अपने अधिकारों को कैसे इस्तेमाल करती हैं ?**

**रेहटांज :** कई तरीकों से. अपनी संसद की श्रम और सामाजिक नीति की समिति में एफ डी जी बी के प्रतिनिधि के रूप से, मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस तथ्य पर प्रभाव डालने में समर्थ हूं कि श्रम सुरक्षा की समस्याओं पर हमेशा आवश्यक ध्यान दिया जाए. यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ट्रेड यूनियनों में 12 हजार श्रम सुरक्षा वालंटियर इंस्पेक्टर और दो लाख 14 हजार श्रम सुरक्षा अधिकारियों के बिना हम श्रम सुरक्षा को इस ऊंचे स्तर तक नही पहुंच सकते थे. श्रमसुरक्षा "राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के विशाल आपसी-निश्चय के" अधिकार का ही एक हिस्सा है जिसे संविधान में ही दर्शाया गया है. इस उद्देश्य के लिये आवश्यक अधिकारों को लेबर कोड (श्रम संहिता) और श्रम सुरक्षा अधिनियमों में अच्छी तरह से व्याख्या की गई है. सह-निश्चय की शुरूआत कानूनी नियमों की परिभाषा में की गई है. इसे योजना में भी दिखाया गया है और इस प्रकार यह दैनिक व्यवहार में एक निश्चित रूप में आती हैं.

**क्या आप इसकी और विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं ?**

**रेहटांज:** उदाहरण के लिए, श्रम सुरक्षा के लिये ट्रेड यूनियनों के सह-निश्चय, पद्धति में श्रम-रक्षा कर्मियों द्वारा संस्थानों में लगातार नियंत्रण दोरे शामिल हैं. प्रत्येक नियन्त्रण दौरे पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें कमियों की सूची दी जाती है और उन्हें समाप्त करने की तारीख मुकर्रर की जाती है. संस्थान या विभागीय ट्रेड यूनियन कमेटी इस रिपोर्ट पर निर्णय लेतीं है और ट्रेड यूनियन के सदस्यों को इससे अवगत कराती हैं. फिर यह रिपोर्ट संस्थान मैनेजर के पास भेज दी जाती है. इस रिपोर्ट को ट्रेड यूनियनों की श्रम सुरक्षा निरीक्षक द्वारा भी प्रयोग में लाया जा सकता है ताकि वे ऐसे उत्तरदायी प्रबंधकों को इस प्रकार खोजी गई कमियों को निर्धारित समय में कानूनीतौर पर ठीक कराने के लिए दे सकें. इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे उत्तरदायी लोग जो कई बार सलाह देने के बावजूद भी अपना कर्त्तव्य पूरा नही करते हैं. उनसे भी जबाव-तलब किया जा सकता है. श्रम सुरक्षा नियमों के विरुद्ध गंभीर अपराधों में, यह श्रम सुरक्षा जांच और औद्योगिक सफाई निरीक्षण या तकनीकी नियंत्रण के निरीक्षण द्वारा कानूनी मुकदमे तक जा सकता है.

**इस समय श्रम सुरक्षा की सीमायें कहां तक हैं ?**

**रेहटांज :** समाजवादी ढ़ांचा होने

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

# लोको कर्मियों के कार्य के अमानवीय घंटे

एल. आर. एस. ए. इस बात की शिकायत कर रही थी की पिछली नवंबर से दस घंटे के कार्य के समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रतिरोध कार्यवाहियां बेरहमी से विक्टमाइजेशन के माध्यम द्वारा दबाई जा रही हैं. यह उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से उन्हें पिछली फरवरी में आंदोलन करना पड़ा था. अब तीन अप्रैल को एक सरकुलर जारी करके रेलवे बोर्ड इसको औपचारिक रूप दे दिया है कि वे पिछले छः महीनों से क्या कर रहे थे. यह सरकुलर ड्यूटी शुरू होने व खत्म होंने के बीच के समय को ड्यूटी के अधिकतम समय के सिद्धांत को नकारता है. और यह इस बात की घोषणा करता है कि किसी भी हालत में स्टाफ ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले रोक नहीं सकता. यह 'जंगल कानून' के सिवाए और कुछ नही है जो 1946 में राजाध्यक्ष फैसले के पहले मौजूद था और इसे तत्कालीन मुख्य श्रम आयुक्त ने 'अमानवीय' होने की संज्ञा दी थी.

## पहला समझौता तोड़ा गया

वेतनमानों की पुनर्रचना पर एल. आर. एस. ए. के साथ जुलाई 1980 में हुए समझौते को भी तोड़ दिया गया है जिसके फलस्वरूप रनिंग अलाउंस के संशोधन पर बुरा असर पड़ा है. इसका असर खासतौर से मट्रोपोलिटन शहरों से उपनगर क्षेत्रों में मोटरकर्मियों और गार्डों पर पड़ा है. एल. आर. एस. ए. की सलाहकार समिति ने लोकोकर्मियों को उन पर थोपी गयी कटौती के बारे में शिक्षित करने का फैसला किया है. सेंट्रल रेलवे की मोटरमैन्ज एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सेक्रेट्री जनरल एस. के. धर को आमंत्रित किया और बातचीत के बाद यह फैसला किया गया कि इस कटौती का खात्मा करने के लिए निचले स्तर से ही एकता कायम की जाए.

ए. आई. एल. आर. एस. ए. की सलाहकार समिति की बैठक 5 जून को बंबई में हुई, और इसने सभी संबद्धताओं के लोको रनिंग स्टाफ के नाम एक अपील जारी की है कि वे एकजुट हों ताकि अमानवीय दास श्रम पद्धति को लागू होने से रोका जा सके.

एल. आर. एस. ए. ने यह नोट किया है कि दमन और विक्टिमाइजेशन के बावजूद संघर्ष की भावना लगातार जारी है. साउथ सेंट्रल रेलवे के डोर्नाकल-काजीपेठ हिस्से के लोको कर्मियों ने दस घंटे के नियत समय से आगे काम करने से इंकार कर दिया जिसके कारण एल. आर. एस. ए. के डिविजनल सचिव को विक्टिमाइज कर दिया गया है.

## विक्टिमाइजेशन की नीति जारी

रेलवे अधिकारी अपनी विक्टिमाइजेशन की नीति के आधार पर ही काम कर रहे हैं. एस. ई. रेलवे में इसने गंभीर रुख अपना लिया है. मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने, रिटायरमैंट और तबादलों के मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण अधिकारियों ने अब अपने हमले डिविजनों में कद्रित कर दिए हैं. बिलासपुर, खरदा रोड, और वाल्टेयर डिविजनों के रेल कर्मचारियों पर गंभीर हमले किए जा रहे हैं. यूनियन के कई महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ताओं का डिविजन से बाहर तबादला कर दिया गया है. उनमें से एक को तो अपनी श्रेणी ही बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है. तबादलों के मामलों में इस तर्क पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है कि उनके रिकार्ड में तबादला हो चुका है इसलिए कोर्ट का आदेश उनपर लागू नही होता. कलकत्ता में सहायता समिति ने ऐसे मामलों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट में लड़ने का फैसला किया है. □

# जो डी आर में औद्योगिक दुर्घटनाओं की कमी

[पृष्ठ तेरह से आगे]

के कारण हमारे देश में एसी कोई सीमायें नहीं हैं. फिर भी यदि लोग ऐसे कारण, जिनसे काम करते समय स्वास्थ्य हानि हो जाती है, खोजने में असफल हो जाते हैं तो कुछ कठिनाई अवश्य हो सकती है. जिस सीमा तक हम इन कारणों को जान पाते हैं वहां तक हम उनके समाप्त करने के लिये कोई न कोई उपाय निकालते हैं. निःसंदेह मानव-व्यवहार द्वारा उत्पन्न औद्योगिक, दुर्घटनाओं को भविष्य में समाजवाद में रहते हुये भी पूरी तरह से नही निकाला जा सकता. फिर भी काम के हालात को सुसंगठित करने के लिए हर काम इस प्रकार किया जा रहा है कि इस प्रकार के अनुचित व्यवहार कभी भी न पनपे. एक तरफ तो श्रम सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगातार शिक्षा-प्रसारण की आवश्यकता है, जिसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी ट्रेड यूनियनों की है, तो दूसरी तरफ जब यह जान लिया जाता है कि दुर्घटनाओं के का 'अनुचित व्यवहार' ही हैं तो इस बात की हमेशा जांच की जाती है कि ऐसी गलतियों को भविष्य में तकनीकी और संगठनात्मक तरीकों से कैसे बचाया जा सकता है. □

—एफ डी जी बी रिव्यू—2/81.


## संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

नीरेन घोष सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

# समूचे भारत में मई दिवस की धूम

सीटू, यू. टी. यू. सी., ए आई आर बी ई ए, ए आई आई ई ए और अन्य संगठनों के नेतृत्व में दिल्ली में मजदूरों का एक जुलूस मोरी गेट से गांधी मैदान गया जहां एक सभा आयोजित की गई थी. सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने इस सभा को संबोधित करते हुए मजदूरों का आह्वान किया कि वे मजदूर वर्ग को कार्य व जीवन यापन के हालात पर इंदिरा सरकार के सभी हमलों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकारों तथा केरल की वाम-जनवादी मोर्चा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकारें देश में जनवाद की स्तंभ हैं और इन सरकारों ने मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा की है. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे इन सरकारों की रक्षा करे व उनकी उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाएं.

दूसरे केंद्रों से भी मई दिवस के समाचार मिले हैं. सोनीपत में आयोजित एक विशाल रैली को सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, एम पी., ने संबोधित किया. जयपुर में कई गेट व क्षेत्र सभाएं आयोजित की गई जिन्हें सीटू सचिव मोहन पुनमिया, प्रहलाद, सुरेश व्यास और अन्यों ने संबोधित किया. अमृतसर में एक सभा में 5,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया और इस सभा को सीटू सचिव एम. के. पंधे ने संबोधित किया. पटना में सीटू, एटक, और यू. टी. यू. सी. ने एक जनप्रदर्शन के माध्यम से राज्य के राजपाल को एक ज्ञापन-पत्र दिया और कई सभाएं आयोजित की गई.

बंबई में एक बहुत ही शानदार संयुक्त रैली आयोजित की गई. मद्रास में भी मई दिवस पर एक विशाल रैली आयोजित हुई. कलकत्ता में मई दिवस रैली में लाखों मजदूरों ने भाग लिया. इसी तरह की रैलियां राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई. कानपुर की मई दिवस रैली को आल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष हरकिशन सिंह सुरजीत ने संबोधित किया. आसाम में पृथकतावादी आंदोलन के नेताओं की धमकियों के बावजूद विभिन्न स्थानों पर मई दिवस सभाएं आयोजित हुई.

केरल में त्रिवेंद्रम, कन्नानौर और अन्य स्थानों पर कई सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई. समूचे देश में मई दिवस रैलियों में मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. राजामुंडरी, पुरनापानी, कोटा, भिलाई, भोपाल, विजयवाड़ा, हैदराबाद, त्रिची, त्रिचूर, कोट्टायम, नागपुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, लखनऊ, मेरठ, पौढ़ी, पीलीभीत, सीतामढ़ी, इटावा, गाजीपुर, बड़हालगंज, गाजियावाद, फरीदाबाद, बंगलोर, अगरतला, वास्को, विशाखापतनम्, आदि अनेक स्थानों से मई दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं. इस साल कुछ उदाहरणों को छोड़कर लगभग सब जगह सभाएं एकजुट तौर पर आयोजित की गई थीं. □

# तमिलनाडु में बागान मजदूरों पर हमले

तमिलनाडु में बागान मजदूर ज्यादा से ज्यादा संगठित हो रहे हैं और बागान मालिकान को न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर रहे हैं. मजदूरों की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर राज्य में बागान प्रबंधकों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया है और बागान मजदूरों के गैर कानूनी विक्टिमाइजेशन का सहारा ले लिया है.

कंचगाडू जया मारूति एस्टेट के चिथरंजी क्षेत्र में प्रबंधकों ने पांच मजदूरों को काम पर लेने से इसलिए मना कर दिया है कि वे यूनियन में शामिल हो गए थे. प्रबंधकों ने गुंडों और बाहरी मजदूरों की भर्ती शुरू कर दी. पुलिस की सक्रिय सहायता से ये गुंडा तत्व मजदूरों पर हमले करते हैं.

20 मई को एस्टेट यूनियन के पीरूमल ने नागरकोआइल में श्रम अधिकारी के समक्ष समझौतावार्ता में भाग लिया था. रात को प्रबंधक के साथ साजिश करके पुलिस ने यूनियन के दफ्तर पर धावा बोल दिया और पीरूमल और यूनियन के अन्य कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. अगले दिन झूठे दोष लगाकर कई और मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें मानकाविलई, अट्टूर, गुंडाविलई, थिरूबट्टार, कलांसेकरम आदि स्थानों से गिरफ्तार किए गए मजदूर भी शामिल हैं.

राज्य सीटू के सचिव जे. हेतचंद्रन, एम. एल. ए. ने इन हमलों की निंदा की है और राज्य सरकार से मांग की है कि इस आतंक को बंद करे तथा गिरफ्तार किए गए मजदूरों को तुरंत रिहा करे. आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) की सचिव विमला रणदिवे ने राज्य मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर इस मामले में 'उचित कार्यवाही' करने का अनुरोध किया है. □

# तमिलनाडु चमड़ा उद्योग के मजदूरों का सम्मेलन

तमिलनाडु चमड़ा उद्योग के मजदूरों का तीसरा राज्य सम्मेलन नार्थ आरकाट जिला में वनियाबाड़ी में 16-17 मई को संपन्न हुआ. राज्य के चमड़ा उद्योग के सभी केंद्रों से 60 महिलाओं सहित 185 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. वी. के. को थांडरमन ने अध्यक्षता की. के. आर. सुंदरम, एम. एल. ए. ने इसका उद्घाटन किया.

एस. ए. थंगाराजन ने उद्योग में काम के हालात और मजदूरों की मांगों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की. आर. उमानाथ, एम. एल. ए., ए. बालासुब्रहनणयम्, पी राममूर्ति, एम.पी., ने प्रतिनिधि व खुले अधिवेशन को संबोधित किया. □

# हरयाणा में पुलिस दमन जारी

हरयाणा में मजदूर बर्बर दमन का सामना कर रहे हैं और मिल मालिकान ने गुंडों की सहायता से राज्य पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके आतंक फैला रखा है. 'सीटू मजदूर' के पिछले अंकों में दमन की कई रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं.

सिरसा में गोपीचंद टैक्सटाइल मिल के मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में और पुलिस दमन के खिलाफ 59 दिन की हड़ताल की. 16 मई को मजदूरों और मिल के प्रबंधकों के बीच हुए समझौते का प्रबंधक खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि प्रबंधक उन सभी मजदूरों को हड़ताल की समाप्ती के बाद वापस नहीं लिया है जिनको लिया जाना चाहिए था. मजदूर कालोनी के दरवाजे मजदूरों के लिए अभी खोले नहीं गए हैं और इसे गुंडा कैंप बना दिया गया है जिसके कारण मजदूरों को काफी कठिनाइयां सहनी पड़ रही हैं. पुलिस और अपनी गुंडा फौज के माध्यम से मजदूरों को आतंकित करके, प्रबंधक नाकामयाबी के साथ मजदूरों की जुझारू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस इसका तमाशा चुपचाप देखती रहती है और तब भी जब मजदूरों पर इसकी उपस्थिति में हमले होते हैं.

हिसार टैक्सटाइल मिल के मजदूरों ने महंगाई भत्ते, बोनस, विक्टिमाइजेशन के सभी मामले खत्म करने आदि की मांगों के समर्थन में 19 मई से हड़ताल कर दी, जबकि प्रबंधक अड़ियल रहे और एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं थे. सीटू की हरयाणा राज्य कमेटी ने 31 मई को एक बयान में अधिकारियों के रवैये की कड़ी निंदा की और तुरंत समझौते की मांग की.

3 मई को भजनलाल सरकार की बर्बर पुलिस ने फरीदाबाद की लखानी रबर के मजदूरों पर लाठीचार्ज किया. मजदूरों की झुग्गियों से उनका सामान लूट लिया गया और उनके परिवारों की महिला सदस्यों व बच्चों पर हमले किए गए. ये मजदूर 18 अप्रैल से फैक्ट्री में तालाबंदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे. 40 से ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार करके झूठे मामलों में फंसा दिया गया.

8 मई को फरीदाबाद में सीटू के कार्यकर्त्ता शत्रुधन द्विवेदी पर समाज-विरोधी तत्वों ने हमला बोल दिया. जब वह पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया तथा पीटना शुरू कर दिया. रात को उसका मित्र विजय कुमार झा उसके बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, उसको भी पीटने के आदेश जारी कर दिए गए. इन दोनों साथियों को रात भर पुलिस स्टेशन में ही रखा गया और मजदूरों में आतंक फैलाने के नजरिये से उनकी रात भर पिटाई होती रही. इन साथियों को गंभीर चोटें आईं.

एम. एंड. एम. इंडस्ट्री, कुंडली (सोनीपत) की महिला कामगार अन्य मजदूरों के साथ मिलकर मजदूरों की यूनियन की उपाध्यक्ष श्यामा वर्मा सहित 17 मजदूरों को बर्खास्त किए जाने के खिलाफ 21 अप्रैल से संघर्षरत थीं. प्रबंधकों ने यूनियन व मजदूरों की जुझारू एकता को तोड़ने के लिए ही इन मजदूरों को बर्खास्त किया था.

उसी दिन से ही मजदूरों ने धरना आयोजित कर रखा था और 22 मई को प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों, जिसमें फैक्ट्री का फोरमैन भी शामिल था, मजदूरों पर घातक हथियारों से हमला बोल दिया. इसके कारण यूनियन की कोषाध्यक्ष कृष्णा और राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गए जबकि कई मजदूरों को चोटें आई.

मजदूरों ने तुरंत प्रतिरोध प्रदर्शन आयोजित किया जो फैक्ट्री गेट पर एक सभा में परिवर्तित हो गया. सभा को संबोधित करते हुए हरयाणा सीटू के महासिचव श्रद्धानंद सोलंकी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री के मालिक व उसके गुंडों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजदूर बड़ी कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

## 20 मई को एक दिन की सफल हड़ताल

सीटू, एटक, एच. एम. एस. व बी. एम. एस. के आह्वान पर हरियाणा के मजदूर वर्ग ने 20 मई को एक दिन की आम हड़ताल की. बल्लभगढ़, गुड़गांव, पानीपत, करनाल, भिवानी, रोहतक, हिसार, सोनीपत, बहादुरगढ़, गन्नौर, बहालगढ़, राई, कुंडली, आदि औद्योगिक नगरों में लाखों मजदूर काम पर नहीं गए और हड़ताल को पूर्ण कामयाबी दी.

ये मजदूर 500 रुपये न्यूनतम वेतन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वापसी, सभी त्रिपक्षीय समितियों में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व, ठेका मजदूर प्रथा की समाप्ति, प्रोविडेंट फंड की तुरंत अदायगी आदि की मांग कर रहे थे. इन मांगों के अलावा मजदूरों ने पुलिस दमन, ले-आफ व तालाबंदी की समाप्ति, विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा किए गए गोलीकांडों की जांच, औद्योगिक विवादों में पुलिस हस्तक्षेप के खात्मा आदि मांग की. □

सीटू के अध्यक्ष बी. टी रणदिवे ने हरयाणा के मजदूरों को बधाई देते हुए उनसे अपील की कि वे 'अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए अपनी इस एकता को कायम रखें और इसे मजबूत बनाएं'. □

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित